

वैश्विक चुनौतियां, वैश्विक समाधान: कुछ टिप्पणियां *

दुव्वरी सुब्बाराव

1. हाल के अनुभव यह बताते हैं कि वैश्वीकरण अद्वितीय अवसर तो उपलब्ध कराता ही है, लेकिन साथ ही अत्यधिक चुनौतियां भी खड़ी करता है। यदि वैश्विक वित्तीय संकट के वर्षों पहले तथाकथित 'ग्रेट मॉडरेशन' की अवधि ने वैश्वीकरण के लाभों को दर्शाया, तो संकट के विध्वंसकारी रूप ने दुष्परिणामों की अपनी कीमत भी दिखा दी। बिल्कुल जैसे कि अर्थव्यवस्था के मामले में मूल्य तय करने वाले और मूल्य स्वीकार करने वाले होते हैं, उसी तरह से अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो वैश्वीकरण की शक्तियों को आकार देती हैं और कुछ ऐसी अर्थव्यवस्थाएं भी हैं जिन्हें वैश्वीकरण की शक्तियों के अनुसार अपने को ढालने के लिए अपनी नीतियों को आकार देना पड़ता है। संकटोत्तर सुधार के प्रयास - चाहे वे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में किए जा रहे हों अथवा अन्य वैश्विक पटलों पर - जैसे बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस), वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी), विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) - इन सभी का उद्देश्य हमारे सामूहिक कल्याण को अधिकतम स्तर पर ले जाने के लिए वैश्वीकरण की शक्तियों का प्रबंधन करना है। इन सुधारों को अनवरत कायम रखने के लिए यह आवश्यक है कि वैश्वीकरण की शक्तियों को आकार देने वाले तथा वैश्वीकरण की शक्तियों के अनुरूप स्वयं को ढालने वालों के स्तर पर ये प्रयास समान रूप से किए जाएं।

वैश्विक संदर्भ में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं

2. इससे पहले कि मैं विशिष्ट मुद्दों की बात करूं, मैं वैश्विक संदर्भ में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर टिप्पणी करना चाहूंगा। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के पक्ष में शक्ति के वैश्विक संतुलन का झुकाव सर्वविदित है। यह उपयोगी होगा कि इस संबंध में कुछ आंकड़े भी दे दिए जाएं। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 2000-10 के दशक में 17 प्रतिशत की कुल वृद्धि की तुलना में आधार वर्ष 2000 में जीडीपी को 100 पर निर्धारित करके, उभरते बाजारों और विकासशील देशों में 82 प्रतिशत की वृद्धि हुई और बीआरआईसी (ब्रजील, रूस, भारत, चीन) में 127 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई। जब हम वैश्विक सकल देशी उत्पाद में हिस्सेदारी पर ध्यान देते हैं तो यह ज्ञात होता है कि, वैश्विक सकल देशी उत्पाद में विकसित अर्थव्यवस्थाओं का अंश वर्ष 2000 के 80 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2010 में 67 प्रतिशत पर आ गया जबकि उभरते बाजारों और विकासशील देशों के अंश में लगभग उतनी ही वृद्धि हुई।

* डॉ. दुव्वरी सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, और भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता द्वारा 16 अप्रैल 2011 को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और वित्तीय समिति (आइएमएफसी), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वाशिंगटन डीसी में दिया गया प्रमुख भाषण।

3. 2010 बहाली का वर्ष रहा है, और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं ने 2010 में वैश्विक वृद्धि में लगभग तीन चौथाई वृद्धि करके बहाली में सहयोग दिया। पिछले वर्ष विश्व व्यापार की लगभग 12 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि के पीछे उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं भी प्रोत्साहन देने वाली शक्ति थीं, जो कि 2009 के 11 प्रतिशत के संकुचन की तुलना में एक प्रभावशाली वापसी है।

4. इन प्रवृत्तियों का डीकपलिंग के विचार पर, जो कि संकट के पूर्व वृद्धिजीवियों में काफी प्रचलित था, एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वास्तव में संकट काल, डीकपलिंग परिकल्पना को प्रामाणिक सिद्ध कर पाने में असफल रहा, क्योंकि सभी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर संकट का विभिन्न मात्राओं में प्रभाव पड़ा। वास्तव में संकट काल ने यह बात पुनः साबित की कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक संभावनाएं व्यापार, वित्त और विश्वास के चैनलों से आपस में जुड़ी हुई हैं।

5. अब मैं विशिष्ट मुद्दों के संबंध में बात करूंगा। इस सत्र के विषय के संदर्भ में मैं पांच विषयों पर बात करूंगा जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

वैश्विक पुनःसंतुलन

6. पहला मुद्दा वैश्विक पुनःसंतुलन का है। वैश्विक पुनःसंतुलन के लिए घाटे की अर्थव्यवस्था वाले देशों से यह अपेक्षित होगा कि वे बचत ज्यादा करें और उपभोग कम, जबकि वृद्धि बरकरार रखने के लिए घरेलू मांग की तुलना में बाह्य मांग पर ज्यादा आश्रित रहें। अधिशेष वाली अर्थव्यवस्थाओं को इन प्रयासों को परिलक्षित करना होगा - बचत कम और खर्चा ज्यादा, और बाह्य मांगों की अपेक्षा आंतरिक मांगों पर ज्यादा निर्भर करें। हमारे समक्ष यह समस्या है कि जबकि घाटे वाली और अधिशेष वाली अर्थव्यवस्थाओं द्वारा किए जाने वाले समायोजनों में संतुलन होना चाहिए किन्तु उन्हें प्राप्त होने वाले इन्सेंटिव असमान होते हैं। पुनःसंतुलन के प्रबंधन के लिए समष्टिआर्थिक नीतियों को लागू करने संबंधी एक साझा समझ की आवश्यकता होगी ताकि समष्टिआर्थिक स्थिरता के संबंध में आने वाली दिक्कतों को न्यूनतम स्तर पर रखा जा सके। इन समायोजनों के कई घटक हैं। मुख्य रूप से विनिमय दरों को आर्थिक मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरूप बने रहने देना और इस बात पर सहमति होना कि व्यापार नीति के उपाय के रूप में मुद्रा उपलब्ध करा कर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए - यह बहुपक्षीय स्तर पर समन्वित दृष्टिकोण का केंद्रबिन्दु होना चाहिए।

पूँजी प्रवाह

7. अब मैं वैश्विक असंतुलनों के दूसरे पक्ष की बात करूंगा - बड़े और अस्थिर पूँजी प्रवाहों की वापसी। चूंकि हाल के महीनों में दुनियाभर में पूँजी प्रवाह काफी संवेदनशील विषय बन गया है इसलिए कुछ सच्चाइयों के बारे में सजग रहना महत्वपूर्ण है। प्रथमतः उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को अपने निवेश योग्य संसाधनों को बढ़ाने के लिए पूँजी प्रवाहों की आवश्यकता होती है किन्तु ऐसे प्रवाहों को दो मानदंड पूरे करने चाहिए : उन्हें स्थिर होना चाहिए; और उन्हें अर्थव्यवस्था की अवशोषण क्षमता के लगभग बराबर होना चाहिए। दूसरी सच्चाई भी हमें अवश्य याद रखनी चाहिए कि पूँजी प्रवाह पुल और पुश (दोनों ही) कारकों द्वारा प्रेरित होते हैं। पुल कारकों में, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की आशाजनक वृद्धि की संभावना, उनकी मुद्रास्फीति की गिरावट की प्रवृत्ति वाली दरें, पूँजी खाते का उदारीकरण, और उन्नत अभिशासन शामिल हैं। पुश कारकों में विकसित अर्थव्यवस्थाओं की सरल मौद्रिक नीतियाँ आती हैं जो उस पूँजी का निर्माण करती हैं जो उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में प्रवाहित होती है।

8. विकसित अर्थव्यवस्थाओं के नीतिगत चयन से जिस सीमा तक बड़े और अस्थिर प्रवाहों का स्पिलओवर होगा उस सीमा तक के पूँजीगत प्रवाहों के प्रबंधन को मात्र उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की समस्या के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उस बोझ को साझा रूप में कैसे वहन किया जाए यह एक बौद्धिक और व्यावहारिक चुनौती है। बौद्धिक चुनौती है, पूँजीगत प्रवाहों को चालित करने वाली शक्तियों की बेहतर समझ पैदा करना, पूँजीगत नियंत्रणों और कार्यों के साथ-साथ किस प्रकार के नीतिगत लिखत किन परिस्थितियों में बनाए जाएं। व्यावहारिक चुनौती है, पूँजी सृजन वाले देशों की घरेलू नीतियों के विदेशों में होने वाले स्पिलओवर के बारे में संगठनात्मक ढांचा तैयार करने की एक साझा समझ तैयार करना और पूँजी प्राप्त करने वाले देशों के नीति संबंधी प्रतिसाद।

9. पूँजी प्रवाहों के प्रबंधन में दो महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं। प्रथमतः हमें यह निर्णय लेना होगा कि बाहरी बातें कितनी महत्वपूर्ण हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें एक वस्तुनिष्ठ आकलन करना होगा कि किन नीतियों से बाहरी बातों के प्रभावों को कम किया जा सकता है। अब जब कि व्यापक रूप से यह स्वीकार कर लिया गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें पूँजी प्रवाह में भारी वृद्धि से निपटने के लिए नियंत्रण नीतिगत प्रतिसाद का एक उचित अंग हो सकते हैं, नीतिनिर्माताओं को समष्टि-आर्थिक, विवेकपूर्ण और पूँजीगत खाता प्रबंधन नीतियाँ अपनाने के संबंध में स्वतंत्रता और विवेक के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें किसी विशिष्ट लिखत से जुड़ी बदनामी के बोध के बिना ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए।

समायोजन प्रक्रिया के लिए ढांचा

10. अब मैं तीसरे मुद्दे की बात करूंगा जो कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता की स्थिति प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने हेतु समायोजन प्रक्रिया के लिए ढांचा है। समायोजन प्रक्रिया को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देशों के एक-एक कदम सामंजस्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़ने में मंददगार हों। मैं इसके दो पक्षों पर बल देना चाहूंगा।

- प्रथमतः अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सर्वेक्षण संबंधी कार्य महत्वपूर्ण है -यह वैश्विक और राष्ट्रीय स्थिरता को बचा कर रखने के संबंध में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। आगामी त्रैवार्षिक सर्वेक्षण समीक्षा उठाए गए कदमों और हाल के अनुभवों को समझने का अवसर प्रदान करती है जिसमें सर्वेक्षण के लिए कानूनी ढांचे की उपयुक्तता भी शामिल है।
- दूसरी बात यह कि आरक्षित मुद्रा को आर्थिक वृद्धि और विकास के संदर्भ में देखना होगा। पूँजी प्रवाहों के अचानक बंद होने और विपरीत परिस्थिति पैदा होने पर आरक्षित निधियाँ जो सुरक्षा प्रदान करती हैं वह आरक्षित निधियों को रखने की अपॉर्चुनिटी लागत से कहीं अधिक होती हैं। संकट काल के अनुभव से काफी हद तक यह साबित हो चुका है। आरक्षित निधियों का उपयुक्त स्तर क्या हो यह देश विशिष्ट पर निर्भर करता है जिसमें व्यावहारिक अनुभव के आधार पर किए गए निर्णय शामिल हैं। स्पष्ट रूप से ऐसे आकलनों के लिए सभी पर लागू होने वाला कोई एक फॉर्मूला नहीं हो सकता है।

वैश्विक आरक्षित मुद्रा

11. मेरे चौथे विषय का संबंध वैश्विक आरक्षित मुद्रा से है। हाल के संकट के फलस्वरूप एक समस्या यह भी पैदा हुई है कि यदि विश्वस्तर पर एक आरक्षित मुद्रा अपना ली जाए तो क्या जटिल चुनौती सामने आएगी। इस समस्या का हल प्राप्त करने संबंधी प्रयासों में, हमारे सामने वैकल्पिक आरक्षित मुद्राओं का एक मीनू हो जो अपेक्षित मानदंडों को पूरा करे यथा - पूर्ण परिवर्तनशीलता; बाजार के मूलभूत सिद्धांतों के द्वारा उनकी विनिमय दर निश्चित हो; विश्व व्यापार में उस मुद्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो; मुद्रा जारी करने वाले देश में वह आसानी से लेनदेन योग्य, खुली हो तथा बड़ा वित्तीय बाजार हो; और उस मुद्रा से संबंधित नीति इतनी विश्वासनीय हो कि संभाव्य निवेशकों में उसके प्रति विश्वास पैदा हो सके। इस बात पर बहस चल रही है कि क्या एसडीआर आरक्षित मुद्रा हो सकता है। एसडीआर द्वारा इस विशिष्ट भूमिका को निभाना आरंभ करने से पूर्व, कई अपेक्षाओं को पूरा करना होगा, जो कि अब सर्वविदित हैं और जिनकी व्याख्या किया जाना इस समय आवश्यक नहीं है। वर्तमान में एसडीआर इन शर्तों को पूरा नहीं करता है। इस तरह से हमारे प्रयास हमें कई मुद्राओं वाले युग की ओर मंद गति ले जा रहे हैं।

संरक्षणवाद

12. अंतिम मुद्दा है संरक्षणवाद। हाल की अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां वैश्वीकरण से संबंधित आशंकाओं के ठीक विपरीत थीं। पहले उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को यह भय था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने पर स्वयं के देश की कल्याणकारी गतिविधियों का नुकसान होगा। इस भय की जगह अब विकसित अर्थव्यवस्थाओं को यह आशंका हो गई है कि वैश्वीकरण का अर्थ है विदेशों में उपलब्ध सस्ते श्रमिकों के चलते अपने देश के लोगों की नौकरियां जाना।

13. कुछ लोगों के मन में यह शंका है कि वर्तमान संकट काल के दौरान यद्यपि खुले संरक्षणवाद का काफी विरोध किया गया, किंतु अप्रकट रूप से संरक्षणवाद बढ़ रहा है। कुल मिलाकर आशय यह है कि आगामी वर्षों में संरक्षणवाद के लिए दबाव बढ़ेगा और संरक्षणवाद नए रूप भी लेगा। जब हम एक साथ अल्पकालिक दबावों का विरोध करेंगे और अपने वैयक्तिक अल्पकालिक लाभों की तुलना में दीर्घकालिक फायदों को सबसे ऊपर रखेंगे तब वैश्विक कल्याण अपने अधिकतम स्तर पर होंगे।

वैश्विक सहयोग

14. अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कुछ भी कहा उस सब का जोर इस बात पर है कि वैश्विक चुनौतियों के लिए वैश्विक समाधान की

आवश्यकता होगी। आज की हमारी सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए वैश्विक सहयोग महत्वपूर्ण है। संकट ने हमें यह सिखाया है कि कोई भी देश अकेला नहीं रह सकता है और कहीं भी होने वाली आर्थिक और वित्तीय गड़बड़ियां सभी देशों में यदि बड़ी समस्या के रूप में नहीं तो आंशिक रूप में जरूर पहुंच सकती हैं। संकट ने हमें यह भी सिखाया है कि वैश्विक आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था में देशों के आपस में अत्यधिक जुड़ाव के चलते अलग-अलग स्तरों पर किए गए उपाय सभी के लिए बदतर परिणाम लाएंगे। आज हमें जिन वैश्विक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वे बहुत जटिल हैं और सरल उपायों से उनका समाधान नहीं किया जा सकता है। उनमें से कई समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर काफी महत्वपूर्ण और अक्सर पीड़ादायक समायोजन करने पड़ेंगे; और ऐसी दुनिया में जो कि देशों में विभाजित है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए प्राकृतिक रूप से कोई छोटी जगह नहीं है। साथ ही, वैश्विक संकट ने यह साबित कर दिया कि एक सत्ता के रूप में वैश्विक अर्थव्यवस्था इससे पहले कभी भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इन सुधारों का केंद्र बिंदु है इसलिए यह सतत रूप से अंतरराष्ट्रीय सहयोग की अगुआई और ताना-बाना बुनने में लगा हुआ है। यह हम सभी की भलाई के लिए है।